मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम को सम्बोधित किया और बताया कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरु हो गया है।

राजस्थान 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने ''निवेश उत्सव'' में कहा, राइज़िंग राजस्थान में हस्ताक्षरित 3 लाख रूपए के एमओयू की ग्राउन्ड ब्रेकिंग हुई

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य में अलग-अलग सैक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से डिज़ायन किए गए 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे।**
- **इस वर्ष 11 और 12 दिसम्बर को दो दिवसीय राइज़िंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन होगा।**

जयपुर, 31 मार्च। सोमवार को जयपुर के एक निजी होटल में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस बार राजस्थान दिवस पर सात दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर महिला, किसान, युवाओं के उत्थान और गरीब कल्याण की कई सौगातें दी गई हैं। इसी कड़ी में, आज हम यहां निवेश उत्सव मना रहे हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होगा।

शर्मा ने कहा कि आज का निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन प्वाइंट ओ) पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मेकैनिज़्म बनाया है। हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई, जो इन एमओयू की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। इस सतत पर्यवेक्षण का ही परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू में से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। कार्यक्रम में इस संबंध में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें उन सभी एमओयू धारकों को शामिल किया गया, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार के साथ 15 मार्च तक एमओयू निष्पादित किए।

शर्मा ने कहा कि हम राजस्थान में 'विकसित राजस्थान 2047' का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए समृद्धि और हमारे उद्यिमयों के लिए अवसरों का एक नया युग साबित होगा।

शर्मा ने कहा कि सरकार 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। इन नए औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि हमारा प्रदेश मैन्यूफैक्चरिंग का पावरहाउस बन सके। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला और दोहा में 14 नए चैप्टर्स खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार इस साल 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन भी करेगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे संबंधित निवेशक मोबाइल पर ही अपने-अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हम राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर निर्णय ले रहे हैं, जिससे वर्ष 2047 तक के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने में राजस्थान अग्रणी राज्य है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 लोगो का बटन दबाकर अनावरण किया तथा कॉन्क्लेव की आधिकारिक घोषणा की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के चैयरमेन आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव खेल एवं युवा मामले भवानी सिंह देथा, रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में निवेशक उपस्थित रहे।

राजशाही समर्थक आंदोलन ने जोर पकड़ा

काठमांडू/रक्सौल, 31 मार्च। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान 'राजा की शरण' में मिल जाने की उम्मीद में, 'लोकतंत्र' को समाप्त कर 'राजतंत्र' की वापसी के लिए संघर्ष शुरू करने वाले दुनिया के पहले देश नेपाल में यह आंदोलन अब पहाड़ से उतरकर मैदान की ओर फैलने लगा है।

भारत के सीमवर्ती राष्ट्र नेपाल में ''राजतंत्र'' की वापसी का आंदोलन बहुत कम समय में ही देशव्यापी विस्तार पाने लगा है। बेरोजगारी और महंगाई से उत्पन्न नाराजगी युवा कंधों पर सवार होकर पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर मैदानों इलाकों में फैलने लगी है। इसके ठीक विपरीत, ''लोकतंत्र'' की स्थापना का आंदोलन मैदानी क्षेत्रों से निकलकर पहाड़ों इलाकों की ओर गया था।

देश की राजधानी काठमांडू से चला आंदोलन हेठौरा और नरायणघाट की सर्पाकार पहाड़ी सड़कों से गुजरकर भारत के सीमावर्ती बीरगंज, विराटनगर, नेपालगंज और जनकपुर के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गया है।

उदयपुर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री गिरिजा व्यास झुलसीं, अहमदाबाद रैफर किया

गणगौर की पूजा के दौरान चुन्नी ने आग पकड़ ली थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर/उदयपुर, 31 मार्च। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री गिरिजा व्यास (79) आरती करते हुए झुलस गईं। गणगौर पूजा के दौरान दीपक से उनकी चुन्नी में आग लग गई। गिरिजा व्यास को उदयपुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनको अहमदाबाद रैफर कर दिया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गिरिजा व्यास के भाई और भतीजे से अहमदाबाद फोन पर बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री रूशिकेश पटेल से बात करके गिरिजा व्यास के बेहतर इलाज के लिए भी चर्चा की।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल से बात करके गिरिजा व्यास के बेहतर इलाज का आग्रह किया।**

व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था। इस दौरान आग लगने की सूचना मिली। घर पहुंचे तो पता चला कि वे गणगौर का पूजन कर रही थीं। इसी दौरान उनकी चुन्नी में आग गई। नीचे जल रहे दीपक के कारण उनकी चुन्नी ने आग पकड़ ली थी। घर में ही काम करने वाले एक व्यक्ति ने उनको संभाला। उनको उदयपुर में निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उन्हें अहमदाबाद रैफर कर दिया गया।

बहू हितांशी शर्मा ने बताया कि गणगौर की पूजा करने के बाद सभी लोग अपने-अपने कामों में लग गए थे। इसी दौरान नीचे जल रहे दीपक से चुन्नी ने आग पकड़ ली। इसके बाद तुरंत मैं और मेरे पति और घर में काम करने वाला बसंत उन्हें अस्पताल लेकर गए।

अप्रैल -जून में देश के 15 राज्य गर्मी से झुलसेंगे

भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया

- **मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 10 दिन में लू चलने की चेतावनी दी**
- **मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है।**

नयी दिल्ली, 31 मार्च। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अप्रैल से जून के बीच सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। इस साल फरवरी के अंत में ही कोंकण, तटीय कर्नाटक में गर्म हवाएं चलने लगी थीं। मार्च में ओडिशा समेत कई राज्यों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की खबरें आईं। अब मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य और पूर्वी भारत के अलावा उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में भी लू का जबरदस्त कहर रहने की आशंका है।आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने को कहा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की आसार हैं। उन्होंने कहा, देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में लू (गर्म हवाएं) वाले दिनों की संख्या पिछली बार से अधिक रहेगी। कुछ राज्यों में लू वाले दिन दोगुना होने की आशंका है।

महापात्र ने कहा, जिन राज्यों में सामान्य से अधिक गर्म हवाएं चलने की संभावना है, उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ , तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भाग शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में इस अवधि के दौरान 10 से 11 दिन लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रमुख ने कहा, अप्रैल में भारत के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

रविवार व अन्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायाधिकरण ने 14 नवंबर, 2014 को यह कहते हुए तकनीकी आधार पर उसका दावा खारिज कर दिया कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम करना साबित नहीं किया है। जिंदल ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि न्यायाधिकरण ने सेवा अवधि की गणना करते समय रविवार और अन्य सवैतनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया, जबकि नियमानुसार सेवा अवधि के बीच यदि कोई सवैतनिक अवकाश आता है तो उसे भी सेवा अवधि में ही शामिल किया जाएगा।

इन अवकाशों को शामिल करने पर याचिकाकर्ता की सेवा अवधि 246 दिन की होती है। न्यायाधिकरण ने आदेश देते समय इसका ध्यान नहीं रखा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी इस संबंध में व्यवस्था दी गई है। हाईकोर्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी नजीर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के मामले में भी यह व्यवस्था थी कि रविवार और अन्य सवैतनिक अवकाशों को भी सेवा अवधि में शामिल माना जाएगा।

'बिहार में अमित शाह सरकार चला रहे हैं'

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश तो सिर्फ मुखौटा हैं

- **जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया ईद मिलन कार्यक्रम में शिरकत की।**

किशनगंज, 31 मार्च। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, सरकार केन्द्रीय मंत्री अमित शाह और उनके अधिकारी चला रहे हैं।

किशोर किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। ईद मिलन कार्यक्रम के बाद किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कुमार खुद सरकार चलाने की स्थिति में नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन्हें 13 करोड़ लोगों के ऊपर बैठा रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, जबकि दिल्ली में बैठी सरकार और उनके अधीन कुछ अधिकारी सरकार चला रहे हैं।

किशोर ने कहा कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं। यदि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए बिना वक्फ कानून पारित किया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ कानून पारित होता है तो इसके लिए भाजपा से ज्यादा कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के सांसद जिम्मेदार होंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि यदि जदयू के सांसद वक्फ के खिलाफ वोट करते हैं तो यह कानून नहीं बन सकता। और यदि वे वक्फ के खिलाफ वोट नहीं करते हैं तो खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी कहना गलत होगा।

पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई आज

- **सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका विचार के लिए स्वीकार कर ली थी।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक इस कानून के तहत न तो कोई केस दर्ज होगा न ही कोई कार्यवाही होगी।**

नयी दिल्ली, 31 मार्च। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार (1 अप्रैल) को प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बनाए रखने को अनिवार्य बनाता है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला एक अप्रैल के लिए लिस्ट किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों को यह आदेश दे कि वे किसी भी पूजा स्थल के मूल धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों।

इसमें अधिनियम की धारा 4(2) को चुनौती दी गई है, जो किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में बदलाव करने संबंधी कार्यवाहियों पर रोक लगाती है और नए मामलों को दर्ज करने पर भी पाबंदी लगाती है। याचिकाकर्ता नितिन उपाध्याय ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि केंद्र सरकार ने इस कानून के माध्यम से न्यायिक उपचार को अवरुद्ध कर अपने विधायी अधिकारों का अतिक्रमण किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेहद अहम आदेश में 12 दिसंबर 2024 को देश की सभी अदालतों को निर्देश दिया था कि वह 1991 के उपासना स्थल (स्पेशल प्रावधान) एक्ट के तहत उपासना स्थल से जुड़े मामले में किसी भी तरह के अंतरिम या फाइनल आदेश पारित न करें।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल

ट्रेन हरियाणा, जींद से सोनीपत रुट पर चलाई जाएगी

- **110 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम यह ट्रेन इकोफ्रैंडली होती है।**

नयी दिल्ली 31 मार्च। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रेन दूसरी ट्रेनों से काफी अलग है। सबसे खास बात है कि ये पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। चेन्नई की इंटीठाल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में इसे तैयार किया गया है। 89 किलोमीटर के इस रूट पर ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ। यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। 1200 हॉर्सपावर की क्षमता वाली यह ट्रेन एक बार में 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी।

रेल मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन सेल-आधारित ट्रेनों के निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसके तहत 35 ऐसी ट्रेनें तैयार की जा रही हैं। 8 कोच वाली यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शामिल होगी। हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और शून्य कार्बन लक्ष्य की ओर बढ़ ने में अहम भूमिका निभाएगी। ट्रायल के दौरान, ट्रेन की तकनीकी क्षमता और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया जाएगा। सफल परीक्षण के बाद इसे नियमित संचालन में लाने की योजना है। चेन्नई की इंटीठाल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) द्वारा निर्मित यह ट्रेन स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण कदम है।

ऑक्सफोर्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कितना लचर था। इस पर उन्हें कोई खेद नहीं था।

इंगलैंड में उन्होंने बेतुका भाषण दिया, उन्होंने कहा, ''मेरे दो पैर हैं, दो हाथ हैं.....'' और इसी तरह अपने अंगों का जिक्र किया, जिससे लोग उलझन में पड़ गए कि वह किस बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में ब्रिटेन के महान योगदान की भी तारीफ की।

एक भारतीय उच्च पदाधिकारी के रूप में, ममता बनर्जी का इंग्लैंड में दिया गया भाषण शर्मनाक था। हालांकि, ममता को विदेश में अपने देश की निंदा करने और उपनिवेशवाद की तारीफ करने का कोई एहसास तक नहीं था।

उन्होंने तो यही जताया, पूरी बैठक के दौरान, भारतीय प्रवासी, विशेष रूप से बंगाली लोग जो वहाँ बसे हुए थे, राज्य के अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की ''हत्या'' के लिए उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे।

ममता बनर्जी का ऑक्सफोर्ड व्याख्यान इंग्लैंड में बंगाल की गंदगी को सार्वजनिक रूप से उजागर करने का एक अयोग्य अवसर बन गया था। यह एक बहुत ही अप्रिय घटना थी।

'मोदी का उत्तराधिकारी ढूंढने की कोई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सेवानिवृत्त किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

इस अटकल को खारिज करते हुये कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होना संभावित है, फड़नवीस ने कहा: ''हमारी संस्कृति में, जब तक पिता जीवित हों, तब तक उत्तराधिकारी की चर्चा अनुचित मानी जाती है। इस बिन्दु पर चर्चा करने का समय अभी नहीं आया है।''

इस बीच, वरिष्ठ आरएसएस नेता सुरेश ''भैयाजी'' जोशी, जो रविवार को नागपुर में ही थे, ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के हटने की चर्चा की जानकारी नहीं है।

राउत ने अपने बयान में कहा कि यह तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को 75 वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य कर दिया जायेगा तथा इस श्रेणी के अन्य नेताओं को भी सेवानिवृत्त होने के संकेत दिये जायेंगे। मोदी इस वर्ष सितम्बर में 75 वर्ष के हो रहे हैं।

राउत ने आगे कहा कि मोदी पिछले 11 वर्षों में कभी भी आरएसएस मुख्यालय नहीं गये, लेकिन वे रविवार को संघ को यह सूचित करने ही गये कि वे अब पद छोड़ रहे हैं। 2014 के बाद मोदी की आरएसएस मुख्यालय की इस पहली यात्रा को इस रूप में देखा जा रहा है कि गत वर्ष के ''उदासीन रिश्तों'' के बाद, अब अपने सैद्धांतिक अभिभावक (आरएसएस) के प्रति भाजपा का रुख बदल गया है, उसमें उष्णता आ गई है।

पार्टी ने कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम एक सदस्य, जीतन राम माँझी, तो इस उम्र-सीमा को पार कर चुके हैं। अस्सी वर्षीय माँझी इस समय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एन्टरप्राइजेज मिनिस्टर हैं। मोदी सहित, अन्य कुछ मंत्री एक या दो साल के अंदर ही 75 वर्ष के हो जायेंगे।

तथापि, मोदी के भविष्य को लेकर चर्चा, मूल रूप से तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल के चुनावों के दौरान ही उस समय शुरु कर दी थी, जब उन्होंने जोर देते हुये कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बनने के लिये तैयार किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की नागपुर-स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय की यात्रा ने उस चर्चा को बड़ा रूप दे दिया है।

आरएसएस को सत्तारूढ़ भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है।

महाराष्ट्र के विपक्षी दल, शिव सेना (यूबीटी) ने मोदी की आरएसएस मुख्यालय की इस यात्रा को हाथों-हाथ ले लिया और संजय राउत ने बयान दे दिया कि आरएसएस ने मोदी को बुलाया था, ताकि उनके उत्तराधिकारी के प्रश्न पर उनसे चर्चा हो सके।

इस बात पर जोर देते हुये कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, राउत ने कहा, ''वे (मोदी जी) आरएसएस मुख्यालय में संभवत: इसलिए गये थे कि वे सितम्बर में होने वाली अपनी सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र लिख सकें।

राउत ने घोषणा की, ''मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा तथा इस पर निर्णय आरएसएस लेगी''

''मैं ऐसा समझता हूँ कि संघ परिवार देश के नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है। पीएम मोदी का समय पूरा हो गया। वे (आरएसएस) परिवर्तन चाहते हैं तथा अगला भाजपा प्रमुख चुनना चाहते हैं।''

राउत के बयान पर त्वरित एवं निश्चयात्मक प्रतिक्रिया दी गई।

जेईई मेन्स परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि 29 मार्च की रात 11 बजे उससे आखिरी बार बातचीत हुई थी। बेटे ने लखनऊ के लिए बस में रिज़र्वेशन भी करा लिया था।

पिता ने भरोसा दिलाया था कि वह उसका सारा सामान पैकर्स एंड मूवर्स के जरिए ले आएंगे, लेकिन इसके बीच ही यह हादसा हो गया। पिता ने बताया कि उज्ज्वल पढ़ाई में ब्रिलिएंट तो नहीं था, लेकिन एवरेज से काफी अच्छा था। कोटा में वह 2 साल से काफी अच्छे से रह रहा था, इसलिए सुसाइड करने की आशंका नहीं थी।

उज्ज्वल के लिए दीपक मिश्रा ने कहा, हमने देखा है, बच्चों में स्ट्रैस है, वे अपनी बात ठीक से नहीं बता पाते हैं। मैंने जब उसे बताया कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ तो शायद उसको यह करना ही आसान लगा।

म्यांमार में अब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गये हैं। म्यांमार ने देश में आये 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप की आपदा के सोमवार को एक सप्ताह के शोक की घोषणा की।

राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने आज यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूकंप से हुई क्षति और जानमाल के नुकसान के प्रति सहानुभूति जताते हुए 31 मार्च से 6 अप्रैल तक की अवधि को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।

तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिल्ली में समायोजित किया जाए या केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में स्थान दिया जाए, ताकि राज्य में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का रास्ता साफ हो सके।

तथापि, अभी तक न तो ए.आई.ए.डी.एम.के. और न ही भाजपा ने गठबंधन के बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन दोनों पार्टियों से संकेत मिल रहे हैं कि डी.एम.के. विरोधी वोटों में विभाजन न हो, यह एक राजनीतिक आवश्यकता है। यही कारण है कि अन्नामलाई के वक्तव्यों से यह समझा जा रहा है कि पार्टी की राज्य इकाई में होने वाले परिवर्तन उन्हें स्वीकार हैं। वे कई बार कह चुके हैं कि केन्द्रीय नेतृत्व उन्हें जो भी भूमिका देगा, उसे वे स्वीकार करेंगे।

दिलचस्प बात यह भी है कि भाजपा के कुछ नेताओं के अन्नामलाई के साथ मतभेद हैं और पार्टी के कुछ वर्गों में उनकी विदाई का स्वागत किया जाएगा। हालांकि, इस समय ये सब अटकलें ही हैं।

ए.आई.ए.डी.एम.के. का रुख स्पष्ट है कि यदि गठबंधन की कोई बातचीत होगी तो वह चुनावों के करीब होगी।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्टालिन ने 2026 के चुनावों के लिए जिस तरह से एक मजबूत रणनीति बनाई है, उसे देखते हुए, ए.आई.ए.डी.एम.के. के लिए इस समय भाजपा के साथ गठबंधन करना राजनीतिक रुप से आत्मघाती हो सकता है। खासकर जबकि स्टालिन ने, भाषा एवं डीलिमिटेशन जैसे दो महत्वपूर्ण एवं भावनात्मक मुद्दों पर भाजपा को तमिल भाषा एवं तमिलनाडु विरोधी विलेन के रुप में प्रोजैक्ट किया है। इन दोनों मुद्दों पर ए.आई.ए.डी.एम.के. को भी डी.एम.के. की तरफ खड़े होने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

अब, स्टालिन के नेतृत्व में राज्य में हुए विकास को प्रभावशाली अभियान का रुप दिया जा रहा है। एक स्थानीय समाचार पत्र ने राज्य के औद्योगिक विकास पर 64 पृष्ठों का विशेष अंक प्रकाशित किया है, जिसमें तमिलनाडु की आर्थिक सफलता के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

स्टालिन ने अपना आक्रामक एजेण्डा शुरु करके अपने प्रतिद्वंदियों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है, जिससे ए.आई.ए.डी.एम.के. रक्षात्मक स्थिति में आ गई है। उसकी स्थिति जटिल हो गई है, क्योंकि वह इस भय से डी.एम.के. द्वारा उठाए गए मुद्दों का विरोध नहीं कर सकती कि कहीं उसे तमिल विरोधी न समझ लिया जाए। इसके अलावा, अन्नाद्रमुक ''दो भाषा नीति'' के विरुद्ध भी कोई रुख नहीं अपना सकती, जिसे उसने स्वयं ही उस समय लागू किया था, जब वह सत्ता में थी।

क्या केरल में विधानसभा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विरोध किया है। इसके साथ ही, उन्होंने पिछले महीने वामपंथ-शासित केरल की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की थी। थरुर को यह कहते हुये उद्धृत किया गया है, ''मैंने किसी न किसी बिन्दु पर सबकी आलोचना की है। मेरे अपने विचार हैं, तथा कभी -कभी मेरे विचार मेरी पार्टी को पसंद नहीं आते। मैं ऐसी स्थिति का सामना लम्बे समय से कर रहा हूँ।''

पिछली बार, लोकसभा के लिये लगातार चौथी बार जीतने के बाद, थरुर ने घोषणा की थी कि यह उनका अंतिम चुनाव है। वे एक बड़ी भूमिका की तलाश में हैं। उनकी महत्वाकांक्षा केरल विधानसभा प्रचार अभियान चलाने की है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता कि वह राज्य इकाई के अन्य नेताओं की नाराजगी की कीमत पर, थरुर को आगे लाये। फिलहाल, पार्टी नेतृत्व संतुलित स्थिति बनाये रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगामी दिनों में, कुछ टूटने की संभावना है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908